राष्ट्रपति के 2022 के अभिभाषण के मुख्य अंश

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 31 जनवरी, 2022 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों को रेखांकित किया। अभिभाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

स्वास्थ्य और कोविड-19

- भारत ने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन्स लगाई हैं। 90% से अधिक वयस्कों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ लग गई है और 70% से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। इसके अतिरिक्त 15-18 वर्ष के किशोरों को वैक्सीनेशन अभियान में शामिल किया गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों (को-मॉरबिडिटी वाले) को ऐहतियाती डोज़ लगानी शुरू कर दी गई हैं।
- देश में इमरजेंसी यूज़ के लिए आठ वैक्सीन्स मंजूर कर दी गई हैं। इनमें से तीन को भारत में ही बनाया जा रहा है और उन्हें इमरजेंसी यूज़ के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुमोदन मिल गया है।
- स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 64,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 80,000 से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस केयर सेंटर्स बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आसान और पहुंच योग्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना के अंतर्गत गरीबों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 8,000 से अधिक जनौषधि केंद्र बनाए गए हैं।
- भारत परंपरागत दवाओं का विश्व का पहला डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर बनाएगा। भारत से 11,000 करोड़ रुपए मूल्य के आयुष उत्पादों का निर्यात किया गया है।

अर्थव्यवस्था और वित्त

- पिछले कई महीनों के दौरान जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक बने हुए हैं।
- अप्रैल और नवंबर 2021 के बीच भारत में 48 बिलियन USD का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 630 बिलियन USD से अधिक हो गया है।
- अप्रैल और दिसंबर 2021 के बीच भारत का माल निर्यात 300 बिलियन USD रहा।
- जन धन खातों, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी के जरिए लोगों को महामारी के दौरान प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का लाभ मिला। 44 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने।

कृषि एवं खाद्य वितरण

- महामारी के दौरान 19 महीनों के लिए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन दिया गया। इस योजना का परिव्यय 2.6 लाख करोड़ रुपए था। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- 2020-21 में किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों का उत्पादन किया। सरकार ने रबी सीजन के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद की है, जिससे लगभग 50 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। खरीफ सीजन के दौरान 900 एलएमटी धान की खरीद की गई, जिससे लगभग 1.3 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के अंतर्गत 11 करोड़ से

शशांक श्रीवास्तव shashank@prsindia.org
रजत अस्थाना rajat@prsindia.org
31 जनवरी, 2022

अधिक किसान परिवारों को 1.8 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करीब आठ करोड़ किसानों को हर्जाने के रूप में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक चुकाए गए।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना के अंतर्गत 64 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता विकसित की गई। बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई।

एमएसएमई, मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार सृजन

- एमएसएमई के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ गारंटीकृत कोलेट्रल फ्री लोन्स की योजना शुरू की। इससे 13.5 लाख एमएसएमई इकाइयों को फायदा हुआ है और 1.5 करोड़ नौकरियां मिली हैं। जून 2021 में सरकार ने क्रेडिट गारंटी को तीन लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। एमएसएमईज़ की नई परिभाषा से छोटे उद्योगों को विस्तार करने में मदद मिल रही है। व्यापारियों (थोक और खुदरा) और फुटपाथी दुकानदारों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लाभ उठाने के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति दी गई है।
- 14 मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। घरेलू मोबाइल निर्माण क्षेत्र में पीएलआई योजना के कारण, भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरर के रूप में उभरा है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार ने सिलिकॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, चिप डिजाइन और संबंधित उद्यमों के लिए 76,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की।
- सरकार ने करीब 4,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सात मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल क्षेत्रों और एपेरल पार्क्स को मंजूरी दी है।
- 2016 से देश के 56 क्षेत्रों में 60,000 स्टार्टअप्स स्थापित किए गए हैं। 2021 में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उभरे हैं और उनमें से प्रत्येक का न्यूनतम मार्केट वैल्यूएशन 7,400 करोड़ रुपए है।

श्रम और रोजगार

- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 28 लाख फुटपाथी दुकानदारों को 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है।
- मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया था। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं।

दक्षता विकास

- दक्ष भारत मिशन के अंतर्गत आईआईटी, जन शिक्षण संस्थानों और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के माध्यम से 2.25 करोड़ युवाओं को दक्ष बनाया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन

- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को शुरू किया गया है।
- भारत में 1.4 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 23 ग्रीन एक्सप्रेसवे और ग्रीन-फील्ड कॉरिडोर सहित लगभग छह लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण प्रगति पर है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने वाला है।
- 2014-21 के दौरान 24,000 किलोमीटर रेलवे मार्ग को बिजलीकृत किया गया। 11 नए मेट्रो मार्ग शुरू किए गए। 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

शहरी और ग्रामीण विकास

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत गरीबों को दो करोड़ पक्के घर मुहैया कराए गए हैं। पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 1.17 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 27,000 गांवों में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 100 किलोमीटर से अधिक की दर से 36,500 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

पर्यावरण

- कोप-26 समिट में सरकार ने 2030 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन तक घटाने की प्रतिबद्धता जताई। भारत 2070 तक शून्य उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
- भारत ने 'ग्रीन ग्रिड इनीशिएटिव: वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' पहल का जिम्मा भी उठाया है। यह विश्व स्तर पर इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड्स का पहला अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है।

महिला और बाल विकास

- महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया गया।
- 2021-22 में बैंकों ने 28 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को 65,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की। सरकार ने महिला स्वयं सहायता के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया और ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें 'बैंकिंग सखी' के रूप में भागीदार बनाया।

अल्पसंख्यक और आदिवासी मामले

- 2014 से सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के 4.5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।
- आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक में एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों का विस्तार किया गया है।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

- 2020-21 में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 87% स्वीकृतियां 'मेक इन इंडिया' श्रेणी से थीं। सशस्त्र बलों ने 209 सैन्य उपकरणों की सूची जारी की है जिन्हें विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। रक्षा उपक्रमों ने 2,800 से अधिक रक्षा उपकरणों की सूची जारी की है जिनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्टरियों को रक्षा क्षेत्र के सात सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठित किया गया है।
- हाल ही में असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कार्बी समूहों के बीच एक समझौता हुआ था। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 70 हो गई है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।